गंगा जल का अधिकतम उपयोग

4264. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री नागमणि:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गंगा नदी में जल की अनुमानित मात्रा कितनी है;

(ख) सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक उद्देश्यों के लिये पृथक-पृथक कितनी-कितनी मात्रा में जल का उपयोग किया जाता है;

(ग) अपयुक्त जल की मात्रा कितनी है जो समुद्र में गिरता है; और

(घ) गंगा जल के अधिकतम उपयोग के लिये क्या-क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) से (ग) भारत में गंगा नदी में अनुमानित वार्षिक प्रवाह 501643 मिलियन क्यूबिक मीटर है। इसमें से, 2,50,000 मिलियन क्यूबिक मीटर मात्रा उपयोग के लिए उपलब्ध होने का अनुमान है। विभिन्न उद्देश्यों के लिए वर्तमान में उपयोग की जा रही जल की मात्रा उपलब्ध नहीं है। तथापि, विभिन्न उद्देश्यों के लिए वर्ष 2000 के लिए प्रेक्षेपित उपयोग निम्नलिखित होगा:—

(i) सिंचाई	—	150764 मि॰ क्यू॰ मी॰
(ii) पेयजल	—	7900 मि॰ क्यू॰ मी॰
(iii) उद्योग (तापीय एवं परमाणु विद्युत केन्द्रों सहित)	—	5870 मि॰ क्यू॰ मी॰
कुल:		164534 मि॰ क्यू॰ मी॰

बंगलादेश को उपयोज्य जल प्रवाह।

(घ) संबंधित राज्य सरकारें गंगा के जल का इष्टतम उपयोग करने के लिए प्रयास कर रही हैं।

गुजरात में भूमिगत जल में रासायनिक तत्व

4265. **श्री गोपाल सिंह जी॰ सोलंकी:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में सात जिलों में भूमिगत जल में पाये जाने वाले रासायनिक तत्वों की मात्रा सुरक्षित जल की अनुज्ञेय सीमा से चार गुणा से भी अधिक है और इस समस्या से 2,00,000 लोग प्रभावित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की पेयजल समस्या के हल के लिये सरकार क्या-क्या कदम उठाने का विचार रखती है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) और (ख) गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर राज्य के 17 जिलों के 191 गांवों में पेय जल की अनुज्ञेय सीमा से 4 गुणा अधिक रासायनिक तत्व पाए गए हैं तथा इससे लगभग 2.40 लाख जनसंख्या प्रभावित है।

(ग) और (घ) 191 गांवों में से लगभग 75 गांव में लोगों की पेय जल समस्या का हल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पहले से ही विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा शेष 116 गांवों को या तो डीफलुओरिडेशन संयंत्रों की स्थापना करके अथवा पेय स्रोतों पर आधारित व्यक्तिगत जल आपूर्ति तथा सामूहिक जल आपूर्ति योजनाओं के अंतर्गत शामिल करने का प्रस्ताव है।

Water-logging problem in Orissa

4266. SHRIMATI JAYANTI PATNAIK: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the problem of water-logging in the State of Orissa;

(b) if so, the steps taken in 8th plan to resolve the problem of water-logging in that State;

(c) whether any fund has been earmarked for the purpose for Ninth Plan; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) Yes, Sir.

(b) A part of the command of Mahanadi has been covered under Orissa Water Resources Consolidation Project which has been sanctioned during the VIII Plan. The activities under the project include rehabilitation and modernisation of existing projects, improving system deficiencies by on farm development works, linking of canals, repairs of offtake points, cross regulators, etc. These activities result in improved water management thus checking the problem of water-logging. Eight irrigation projects of the State were also taken up under the National Water Management Project (NWMP) with the objective of upgrading the system covering an area of 1.10 lakh hectare.

Steps have also been taken to formulate the Mahanadi Delta Development Plan by the State Government which envisages drainage improvement, flood control, canal modernisation, command area development, ground water development, research and development etc.

Moreover, ten projects of the State have been covered under Centrally Sponsored Command Area Development Programme. Activities under the Programme like construction of field channels and field drains, land levelling and shaping, enforcement of warabandi, promotion of conjuctive use of surface and ground water, introduction of suitable cropping pattern, controlled irrigation at the farm level help in checking water-logging. To propagate scientific techniques of irrigation among farmers to check water-logging, adaptive trials, demonstrations and training have also been taken up under the Programme. During the 8th Plan, Rs. 17.17 crore has been released to the State Government for the Command Area Development Programme. Recently, a item relating to reclamation of water-logged areas has been included under the Programme under which Central assistance is admissible.

(c) and (d) The Ninth Plan is yet to be finalised.

Revival of irrigation projects in Tamil Nadu

4267. SHRI N. THALAVAI SUNDARAM: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of irrigation projects in the country have not been properly maintained;

(b) whether a number of such projects in Tamil Nadu are required to be reviewed as very urgent basis;

(c) if so, the names and details of such projects; and

(d) the steps taken or proposed to be taken for reviewing and properly maintaining projects?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) The Government of Tamil Nadu is implementing a World Bank assisted Project namely Tamil Nadu Water Resources Consolidated Project which aims to improve the productivity and sustainability of Tamil Nadu Irrigation Sector by rehabilitation and modernisation of 43 existing irrigation structures. The latest estimated cost of the project is Rs. 1143.30 crores and Rs. 13.18 crores has been spent upto 3/96. Expenditure incurred by the State Government during 1996-97 is Rs. 2.09 crores. The outlay proposed by the State Government for 1997-98 is Rs. 170 crores. The project is reviewed by the Central Water Commission on quarterly basis.